खण्ड: 2, अंक: 5 मई 2019

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

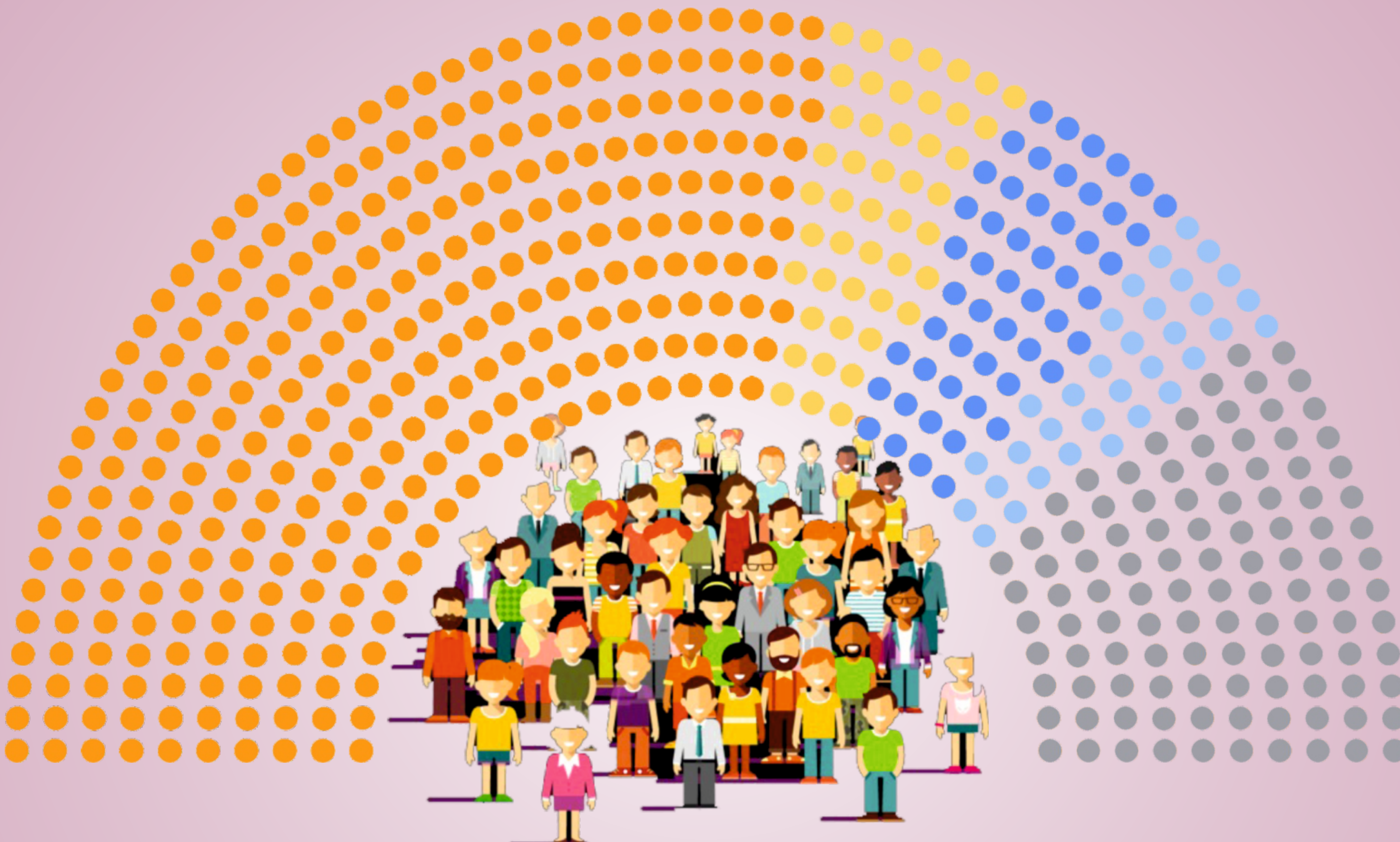

लोक सभा 2019: चुनाव विश्लेषण

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2019

रूपाकंनः आर किशोर

संश्लेषण

लोक सभा 2019: चुनाव विश्लेषण

अनुक्रमिका

सम्पादकीय i-ii

1. लोक सभा 2019 चुनाव परिणामः एक विश्लेषण – राम किशोर 1–3

2. जनादेशः सबक और संदेश – डॉ. अंजनी कुमार झा 4–6

3. भारतीय संसद एवं लैंगिक समानताः एक चुनावी विश्लेषण – रजनी 7–10

4. चुनाव में मोदी को राजनैतिक कूटनीति एवं विपक्ष – जसदीप कौर 11–14

5. 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की भूमिका का विश्लेषण – काजल 15–17

सम्पादकीय

हम अति हर्ष सहित विकासशील राज्य शोध केन्द्र, दिल्लो विश्वविद्यालय की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के वर्ष 2019 के पंचम अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित कर रहे हैं। वर्ष 2018 से प्रत्येक माह के समसामयिक विषय को समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों के मौलिक लेखों द्वारा शाध वास्तविकताओं के प्रकटीकरण का केन्द्र का यह अविरल प्रयास अत्यंत सराहनीय रहा है। शोध निरंतरता की इस कड़ी में संश्लेषण का अब तक का यह दसवां अंक प्रस्तुत करते हुए हमें आत्मिक संतुष्टि एवं शोध तृप्ति का आभास हो रहा है।

वर्ष 2019 का मई माह 17वीं लोक सभा के चुनाव परिणाम पर केन्द्रित रहा। समस्त राजनीतिक दलों एवं चुनाव पंडितों द्वारा नई सरकार के गठन की संभवानाएं तथा अटकलें चुनाव आयोग के औपचारिक निर्णय पर आधारित थी। जहां अधिकांश चुनाव विश्लेषक किसी भो दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलते दिखा रहे थे वहीं मुख्य राजनीतिक दलों ने अपनी–अपनी स्पष्ट, समर्थ एवं स्थायी सरकार बनने व बनाने का अध्यर्थन प्रारंभ से ही प्रस्तुत कर दिया था। चुनाव आयोग द्वारा घोषित 17वीं लोक सभा का परिणाम केन्द्रिय एवं राज्यीय दलों के अखिल भारतीय समावेशन अथवा क्षेत्रीय निरुपण के मध्य एक संघर्ष का भी प्रतिवर्तन था।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'लोक सभा 2019ः चुनाव विश्लेषण' विषय पर लेख आमंत्रित किये। पांच उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख न केवल 17वीं लोक सभी चुनाव के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत कर रहे हैं अपितु भारतोय चुनावी लोकतंत्र की परिवर्तनीय प्रकृति का भी अवलोकन करने का प्रयास कर रहे हैं।

संश्लेषण के इस अंक के समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ भारतीय राजनीति के सामाजिक व आर्थिक जीवन से संबंधित आधारभूत बिंदुओं को भी प्रकट करते हैं। लेखकों के विचार स्वतंत्र चिंतन के परिचायक हैं तथा सम्पादकीय मंडल ने इनकी मौलिकता को संपादन के माध्यम से किसी भी प्रकार प्रभावित व परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है। व्यक्तिगत लेखों में प्रस्तुत तथ्य एवं मत लेखकों की रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदशित करते हैं।

संश्लेषण के इस अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम वर्ष 2019 के जून माह के अपने षष्टम समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणवत्ता लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

शुक्रवार, 14 जून 2019

1

लोक सभा 2019 चुनाव परिणामः एक विश्लेषण

राम किशोर

शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

लोक सभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 की भांति अथवा अधिक सीटों के साथ विजय प्राप्त की है। नरेंद्र मोदी की पार्टी बी.जे.पी. ने न केवल पूर्व चुनाव के मुकाबले अपनी सीटें बढ़ा ली हैं अपितु एन.डी.ए. में सम्मिलित उसके सहयोगी दलों ने भी बढ़त प्राप्त की है। नरेंद्र मोदी दीर्घकालीन रणनीति एवं देश के विकास के लिए लोगों की स्थिर सरकार का आकांक्षा ने उनके विजय का मार्ग प्रशस्त किया है जिनको हम निम्नाकिंत बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पूर्व में लगभग तीन दशकों में देश ने गठबंधन वाली अस्थिर सरकारों के कई दौर देखे, इन सरकारों की मजबूरियां देखीं और नीतियों स हटकर किए गए समझौते भी देखे। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई, बीजेपी ने चूंकि चुनाव एन.डी.ए. गठबंधन के साथ लड़ा था इसलिए गठबंधन धर्म निभाते हुए एन.डी.ए. के घटक दलों को भी सरकार में सम्मिलित किया। इस गठबंधन में बी.जे.पी. के सामने कई अवसर आए जब एन.डी.ए. के घटक दलों का दबाव उसे सहना पड़ा परंतु बी.जे.पी. सशक्त थी इसलिए उसे इन दबावों के सामने असहाय नहीं होना पड़ा। यही कारण है कि पिछले एक–डेढ़ वर्ष में एन.डी.ए. से उसके कुछ घटक दलों ने संबंध समाप्त कर लिया। नरेंद्र मोदी देश के लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल हुए कि स्थिर सरकार देने में केवल बी.जे.पी. ही योग्य पार्टी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी पार्टी बी.जे.पी. ने लोक सभा चुनाव 2014 में विजय प्राप्त करने के पश्चात् ही 2019 की तैयारी आरम्भ कर दी थी, उन्होंने दूरदर्शिता अपनाते हुए दीर्घकालीन रणनीति बनाई। देश भर में राजनीतिक स्थितियों, बी.जे.पी. के जनाधार एवं विपक्षी दलों की दुर्बलताओं एवं दोषों को लोगों के समक्ष रखकर बी.जे.पी. न अपनी रणनीतिक योजनाएं बनाईं। बी.जे.पी. गुजरात, महाराष्ट्र के अतिरिक्त हिंदी पट्टी के उत्तर भारत के राज्यों को लेकर आशस्त थी। यू.पी. के विधानसभा चुनाव के परिणामों से उसका यह विश्वास और सुदृढ़ हुआ परंतु इसके पश्चात् मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने बी.जे.

पी. को झटका दिया, यद्यपि इन राज्यों में बी.जे.पी. और कांग्रेस को प्राप्त मतों के प्रतिशत में कम अंतर ने उसे भविष्य को लेकर अधिक चिंतित नहीं होने दिया।उत्तर प्रदेश में मोदी की ब.स. पा. प्रमुख मायावती एवं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय नेताओं से सीधी भिड़ंत थी। अनुमान लगाया जा रहा था कि यू.पी. में इस चुनाव में बी.जे.पी. पिछले चुनाव जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। पिछले चुनाव में बी.जे.पी. को प्रदेश की 80 में से 71 सीटों पर सफलता मिली थी, इस बार वह 62 सीटों पर आगे रही। यू.पी. की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत महत्व रखते हैं। चाहे स.पा. एवं ब.स.पा. जैसे बड़े दल हो या फिर अपना दल, रा.लो.द. जैसी छोटी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हों, सबका अपना वोट बैंक ह जिसका प्रमुख आधार जाति ही है। बी.जे.पी. किसी जाति को आधार बनाकर चुनाव मैदान में नहीं उतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही बी.जे.पी. उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण में सेंध लगाकर अपनी राह बनाने में सफल हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में बहत मेहनत की जिस कारण बी.जे.पी. पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गई। अरुणाचल प्रदेश में उसने दोनों सीटों पर विजय प्राप्त कर लीं। असम में 14 में से 9 सीटें जीतीं। मणिपुर की कुल दो में से एक सीट पर बी.जे.पी. ने विजय प्राप्त की। त्रिपुरा की दोनों सीटें बी.जे.पी. ने हासिल कर लीं। पूर्व के आम चुनाव में बो.जे.पी. को सभी पूवांत्तर राज्यों में केवल आठ सीटें प्राप्त हुई थीं, परंतु इस बार बी.जे.पी. ने यहां की 14 सीटों पर विजय प्राप्त की है। तृणमूल कांग्रेस के गढ़ पश्चिम बंगाल और बीजू जनता दल के मजबूत प्रभाव वाले ओडिशा में पिछले लोक सभा चुनाव में बी.जे.पी. को निराशा प्राप्त हुई थी।

पश्चिम बंगाल में 2014 में कुल 42 सीटों में से बी.जे.पी. को मात्र दो सीटें मिली थीं। ओडिशा में 21 लोक सभा सीटों में से 20 सीटें बी.जे.डी. को केवल एक सीट बी.जे.पी. को मिली थी। बी.जे.पी. ने इस बार 'लुक ईस्ट' की रणनीति पर काम करते हुए ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इन दोनों राज्यों में बी.जे.पी. का जनाधार बढ़ा है। बंगाल में इस बार तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को मोदी लहर का सामना करना पड़ा। बी.जे.पी. ने ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह केवल मुसलमानों की चिंता करती हैं, हिंदुओं की नहीं. चुनावी राणनीति के अंतर्गत हिंदू मतों को एकजुट करने का माहौल बनाने में बी.जे.पी सफल हो गई। ओडिसा राज्य में विधान सभा चुनाव भी लोक सभा चुनाव के साथ हुए। विधान सभा चुनाव में बीजू जनता दल ने एक बार फिर बहुमत प्राप्त कर

लिया और उसने 146 सीटों में से 103 सीटों पर विजय प्राप्त कर ली। यह ओडिशा में नवीन पटनायक की स्वीकार्यता को प्रमाणित करने वाला मतदाताओं का निर्णय है। मतदाताओं का यह निर्णय कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देने की बात की पुष्टि करने वाला है। अर्थात राज्य में लोगों को बीजू जनता दल से कोई समस्या नहीं है लेकिन केंद्र में वे प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हैं। दिल्ली में पिछली बार की तरह इस बार भी बी.जे.पी. ने सातों लोक सभा सीटें जीत प्राप्त की हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के विरोध के फलस्वरूप सत्ता में आए थे। इस लोक सभा चुनाव से पहले वह उसी कांग्रेस से गठबंधन की जी तोड़ कोशिश करते रहे। दिल्ली की जनता को उनका अपने सिद्धांतों से हटना और उनका ढुलमुल व्यवहार पसंद नहीं आया। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ और कांग्रेस ने अपने बल पर चुनाव लड़ा। उधर बी.जे.पी. ने केजरीवाल को उनके व्यवहार को लेकर जमकर निशाना बनाया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपस में एक–दूसरे के मत काटकर बी.जे.पी. की विजय का रास्ता प्रशस्त कर दिया।

मोदी और उनकी पार्टी बी.जे.पी. 2019 के लोक सभा चुनाव में जहां पूर्वोत्तर में विस्तार किया, वहीं दक्षिण भारत में भी पार्टी को विस्तारित करने का प्रयास किया। तेलंगाना में बी.जे.पी. को 2014 में 8.50 प्रतिशत मत मिले थे, इस बार उसे यहां 19 प्रतिशत से अधिक मत मिले हैं, और कर्नाटक में बी.जे.पी. ने विजय प्राप्त की है, यहां राज्य में सत्तासीन जे.डी.एस.–कांग्रेस को 28 में से सिर्फ दो सीटें प्राप्त हुई हैं। अन्य 26 सीटों पर बी.जे.पी. ने विजय प्राप्त की है। यद्यपि केरल और तमिलनाडु के परिणाम बी.ज.पी. के लिए निराश करने वाले हैं। तमिलनाडु में केवल एक सीट पर बी.जे.पी. की सहयोगी ए.आई.ए.डी.एम.के. ने विजय प्राप्त की है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मई 2019 में हुए लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रोय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.एं.) को वर्ष 2014 में हुए लोक सभा चुनावों की अपेक्षा अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं जिसमें मुख्यतः विपक्ष का अशक्त होना, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अतर्राष्ट्रीय नेता के रूप मे स्वीकार्यता, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय, हिन्दू राष्ट्रवाद एवं पूव के पाँच वर्षो के शासन में विभिन्न सार्वजनिक नीतियों (उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आयुषमान योजना आदि) की घोषणाओ का प्रमुख योगदान रहा है।

♦♦♦♦♦

2

जनादेशः सबक और संदेश

डॉ. अंजनी कुमार झा

सहायक प्रध्यापक, विवेकानंद स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन

मुद्दाविहीन लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली अप्रत्याशित जीत के कई मायने भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक चुनाव प्रचार शैली के आगे भले ही राहुल गांधी टिक न सके किंतु यक्ष प्रश्न है कि चुनाव समर में विपक्षी बिना मुद्दे के कैसे लड़े? वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले दल ठीक चुनाव के पूर्व टिकट में साझेदारी कर भाजपा के विरुद्ध लड़ी। और परिणाम घोषित हाते ही फिर जुदा हो गई।

क्या देश में सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर जवाब नहीं है तो आखिर क्यों कोई मुद्दा सुर्खियां बटोर नहीं पाया? कुछ विश्लेषक मीडिया को 'मैनेज' बताते हैं, पर यह सत्य नहीं है। पहले की भांति मुद्दे इस बार भी जीवित और जीवंत थे, किंतु खास तौर पर टी.वी. और वर्चुअल मीडिया ने इसे अपने स्क्रीन से ओझल कर दिया। मोदी की लंबी फुटेज और भीड़ को यथार्थ बताया जाने लगा जो ज्योतिषीय भविष्यवाणी की भांति सटीक रहा।

आकमणकारी, आक्रामक सत्तारूढ़ भाजपा के मोदी शाह योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे थे। जनता के वर्गीय क्षेत्रीय और जातिगत आचार पर जुमले वह मुद्दे गढ़े गए। मीडिया 'मैनेज' होता चला गया जबकि कांग्रेस अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देती रही। इसे राहुल और कहीं प्रियंका ने जनता को कहा। आरोप–प्रत्यारोप और आलोचना निंदा के घटाटोप में कभी देश का सबसे बड़ा दल कही जाने वाली कांग्रेस के विपक्ष के योग्य भी सांसद संख्या पूरा नहीं कर सकी। सपा, बसपा, राजद का भी यही हश्र रहा।

क्षेत्रीय दल पूरे देश में सिकुड़ गए इसका निहितार्थ यह कतई नहीं है कि महंगाई कम हो गई बेरोजगारी और गरीबी दूर हो गई। अब किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। अर्थात समस्या तो जस की तस है। चाहे भ्रष्टाचार पर बात करें या सामाजिक विषमता पर कुछ परिवर्तन दिखा नहीं। चूंकी भाजपा को पूर्व के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार सीटें काफी ज्यादा मिली

तो यही कारण कहा जा रहा है कि प्रचंड बहुमत मोदी शासन के उल्लेखनीय कार्यों के कारण मिला। यह टी.वी. चैनलों के फैलाये हुए प्रोपेगंडा है। विपक्ष औंधे मुंह गिरा और आवाम के पास विकल्प नहीं था। उसे विपक्ष पर विश्वास नहीं जमा, जनता को स्थिर सरकार चाहिए जिसे भाजपा पूरी करती दिखी और वहीं सिमट चुकी राहुल की कांग्रेस पर भरोसा नहीं बन पाया, इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि भाजपा की अच्छे प्रस्तुतिकरण के कारण जनमत मिला। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उन में सक्षम नेतृत्व ही सफल हुआ। नवीन पटनायक से लेकर जगन रेड्डी तक उदाहरण है।

मोदी के संकल्प और ऊर्जा को देखते हुए लगता है कि यह आरोहण काल अभी 5 वर्ष और चलेगा। कांग्रेस की विचारधारा ही उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। नेहरू ने गांधी जी की खड़ी की गई कांग्रेस को अपने विचारों के अनुरूप ढ़ालने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में उभरी नेतृत्व की पूरी पीढ़ी को शक्तिहीन कर दिया। जिसे पहले इंदिरा और अब राहुल द्वारा दोहराया जा रहा हैं। 2009 का चुनाव पेड न्यूज के लिए कलंकित हुआ। उसमें पत्रकारों की जो भूमिका थी, वह उनके संस्थान के भ्रष्ट हो जाने के कारण थी। 2019 के चुनाव में झूटी खबर को कुछ पत्रकारों ने अपने लाभ के लिए चलाया।

पहली बार वोट डालने वाले वोटरों तक पहुंचने का प्रधानमंत्री का प्रयास रंग लाया। यह बात देश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सी.आर. पटेल ने कह कर सबको चौंका दिया। चहुंमुखी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा का नारा भारी पड़ा इसलिए यह 'राफेल' बोफोर्स बन कर नहीं बरसा। मोदी ने राजनीति में एक नया विमर्श गढ़ा। उन्होंने राजनीति को जातिवादी खाते से निकालकर जनवादी अर्थात वर्गीय खाते में डाल दिया। जनादेश में सभी दलों के लिए संदेश लेने को जोड़ना पुराने को जोड़ें रखना हैं।

अनुभव और ऊर्जा का समन्वय, मिथक को तोड़ना, वाद को धराशायी हो जाना, करना इनका संदेश है। देश हित में साहसिक निर्णय लेने चाहिए। अब मोदी के जादू से हर स्तर पर अपेक्षाएं बड़ी हैं परिणाम के बाद राजनीतिक मुहावरे बदल गए दिल से लड़े गए 1977' के चुनाव में इंदिरा परास्त हुई दिल बदला तो फिर वह सिहासन पर आरूढ़ हो गई।

1962' का चुनाव ने परिवर्तन को थोड़ा रोका किंतु इसे 1967 में परिवर्तित किया गया इसलिए कांग्रेसी गैर कांग्रेसी सरकार के अधिकतर प्रयोग हुए परंतु उसके स्थान पर आज भाजपा के

भाजपा राणनीति की है परिणाम भले ही किसी के लिए अत्यंत सुखदायक तो अन्यत्र के लिए विस्मयकारी है परंतु ईमानदारी से किए गए, कार्य ही चिरस्थाई होगें। नारे, जुमले, वायदे, केवल धर्म आने के लिए है। इसलिए, यह चुनाव कई सबक भी दे गया।

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

3

भारतीय संसद और लैंगिक समानताः एक चुनावी विश्लेषण

रजनी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत के सविधान में दिए गए अनुच्छेद 14 और 19 जो भारतीयों को समानता के साथ स्वतंत्रता प्रदान करते है जिसके द्वारा मानव व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से अपना विकास करने की ओर अग्रसर होता है परंतु भारत की संसद अभी भी लैंगिक समानता के उचित उपाय से काफी दूरी पर है, लेकिन निस्संदेह, इसने प्रगति की है। भारत की संसद के लिए दौड़ने वाली महिलाएं दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कवायद में मुश्किल से एक झपकी लेती दिखाई देती हैं।

क्योंकि भारत में 2019 में होने वाले चुनाव भारत के एतिहासिक चुनावों से कुछ अलग और उच्च दिशा की ओर प्रवृत्त होते दिखाई देते है जहां चुनावों के विश्लेषण में महिला की भागेदारी को एक सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होते देखा जा सकता है जहां महिलाओं का वोट करने से लेकर भारतीय संसद में करने वाली भागीदारी तक में उच्च स्थान को संबोधित करते हुए देखा जा सकता है। क्योंकि भारत मे होने वाले चुनाव आयोग के आंकड़ों के आधार पर चुनाव के परिणामों के भंडार में लोक सभा के अनुसार, सभी 542 सीटों में से 14ः या 17 वीं लोकसभा (संसद का निचला सदन) में महिलाओं का उच्चतम प्रतिनिधित्व को दर्शाया गया है (ईसीआई की रिपोर्ट के अनुसार)।

एतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कहना असत्य न होगा की 1952 में पहली लोकसभा में एक प्रकार से या यों कहे की व्यवस्थित ढंग से संसद (सांसदों) में होन वाली महिला सदस्यों की हिस्सेदारी या भागेदारी 5ः से अधिक देखने को मिलती है। परंतु 2019 में होने वाले चुनाव में कुछ सप्ताह पहले ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी शिवसेना में शामिल होने वाली कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी के द्वारा स्पष्ट किया गया कि चुनावों के दौरान महिलाओं की, पुरुषों की तुलना में बेहतर जीत या भागेदारी में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। 2019 में, 715 से अधिक महिला उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव बनाम 7334 पुरुषों का

चुनाव लड़ा– 10: महिलाओं ने पुरुषों के 6: के विपरीत जीत हासिल की। इसी प्रकार कुछ बड़े राज्यों में महिलाओं की अधिक संख्या देखी गई, क्वाट्र्ज ने लोक सभा डेटा शो का विश्लेषण किया। 80 सीटों के साथ भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक महिलाओं का चयन किया।

[1]

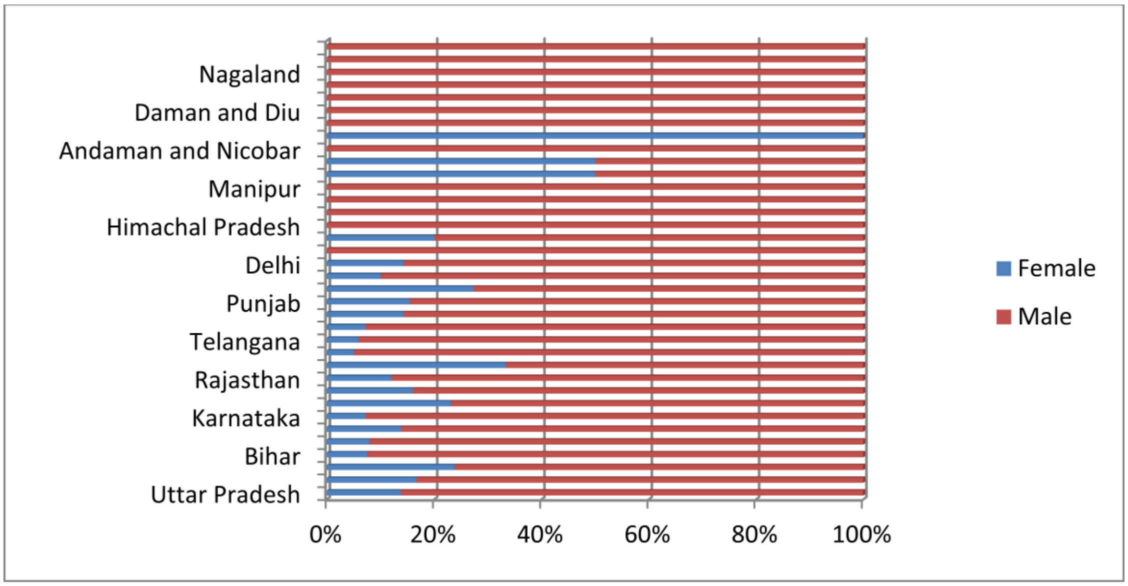

राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी समान अधिकारों की बढ़ती मांग से जुड़ी है। आई.एन.सी ने 1990 के दशक तक सत्ता संभाली थी। जब कांग्रेस कल्याणकारी राजनीति से दूर चली गई, तो अन्य दलों ने अपने एजेंडे के केंद्र के रूप में गरीबी का उपयोग कर कांग्रेस को चुनौती देने के लिए उठीं। प्छब ने 2004 में महिलाओं की भागीदारी की मदद से सत्ता हासिल की और दल के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए 33: कोटा लागू करके महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। जून 2009 में, प्छब ने लोकसभा के पहले स्पीकर बनने के लिए एक महिला को नामित किया, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के चुनाव का भी समर्थन किया। महिलाएं भाजपा की शुरुआती स्थापना में शामिल थीं।

भाजपा ने महिलाओं के नेतृत्व कार्यक्रम, महिला उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता, और दल नेतृत्व के पदों पर महिलाओं के लिए 33: आरक्षण लागू करके महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित किया है। भाजपा ने धर्म की परवाह किए बिना महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों का विस्तार करने के लिए समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके

[1] Data: Trivedi Centre For Political Data

महिलाओं का समर्थन प्राप्त किया है। उन्होंने भारतीय महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ भी बात की। ब्च्प् ने लैंगिक असमानता के मुद्दों का भी समर्थन किया है, जिसमें 'नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन' के माध्यम से हिंसा निकिता एक्लू के मुद्दों को संबोधित करना शामिल है।

1990 से 10–12ः महिलाओं की सदस्यता के साथ राजनीतिक दलों में महिलाओं की भागीदारी कम रही। भारतीय महिलाओं ने भी अपने स्वयं के राजनीतिक दलों के गठन के लिए पहल की है, और 2007 में, 'यूनाइटेड वुमन फ्रंट पार्टी' बनाई गई थी, और संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 50ः तक बढ़ाने की वकालत की थी। अधिकतर महिलाएं केवल भारत के चार राजनीतिक दलों पर शासन करती हैं।

1980–1970 तक, 4.3ः उम्मीदवारों और 70ः चुनावी दौड़ में कोई महिला उम्मीदवार नहीं थी। 2013 तक, यह बताया गया है कि संसद के सदस्य 11ः लोकसभा में महिलाएं थीं और 10.6ः राज्यसभा में थीं। इसी प्रकार चुनावों में होने चाले विकास में आज महिलाओं की संख्या एक वोटर और एक प्रतिनिधि के दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनने की ओर अग्रसर है।

'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' के विश्लेषण के अनुसार, 2019 के आम चुनावों में 700 से अधिक महिला उम्मीदवारों के प्रोफाइल इस प्रकार हैंः–

1. 396 महिला उम्मीदवारों ने स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की। यह कुल का आधा है।
2. 531 की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच है। उनमें से एक चौथाई की आयु 51 से 80 वर्ष के बीच थी। सबसे कम उम्र में बीजू जनता दल (भाजपा) की 25 वर्षीय चंद्रानी मुर्मू थीं, जो ओडिशा के क्योंझर से जीती थीं।
3. इनमें कुछ उम्मीदवारों पर 110 आपराधिक मामले दर्ज थे। 78 तक गंभीर आरोप लगे।
4. 255 करोड़पति महिला उम्मीदवार शामिल है। महिला उम्मीदवारों की औसत संपत्ति रु. 5.63 करोड़ (+ 810,945) थी। हेमा मालिनी, जो मथुरा, उत्तर प्रदेश की दो बार की विजेता रही हैं, ने 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का सबसे बड़ा मूल्य अर्जित किया।

इसी प्रकार स्मृति ईरानी, जिन्होंने अपने पारंपरिक घरेलू मैदान अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया था, उन सभी के सबस बड़े विजेता के रूप में शुरुआत की जा रही है। महात्मा

गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने वाले मालेगांव विस्फोट के आरोपी प्रज्ञा ठाकुर शायद उनमें से सबसे विवादास्पद हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत का चित्र स्त्रियों की ओर से परिवर्तित हो रहा है जिसका प्रारूप सकारात्मक है। और यह आने वाले समय में या यों कहे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनहरे अवसर के समान होगी। जिसे अधिक आगे की आवश्यकता है और सरकार तथा समाज के द्वारा इस पर कार्य किया जाना आवश्यक है।

♦♦♦♦♦

4

चुनाव में मोदी को राजनैतिक कूटनीति एवं विपक्ष

जसदीप कौर

शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

विश्व के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश भारत में सवा अरब की आबादी के साथ 11 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग के निर्देशन में एक चुनावी मैराथन प्रारंभ हुई जिसको 7 चरणों में पूरा किया गया। अंत में जो परिणाम जारी हुए उसने भारत सहित सम्पूर्ण विश्व के चुनाव विश्लेषकों सहित आम जनता सभी को एक बार पुनः आश्चर्य में डाल दिया है । जिसमे कि भारतीय जनता पार्टी 37 प्रतिशत से आधिक मतों के साथ एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विजेता बनकर उभरी है ।

इस चुनाव में कुल मिलाकर बीजेपी को लगभग 40 प्रतिशत के करीब वोट प्राप्त हुए जो कि सन 1980 के समय के बाद से किसी भी लाकसभा चुनाव में दल द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च वोट शयर है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने लगभग 45 प्रतिशत का संचयी वोट शेयर अर्जित किया है जो कि 2014 में एनडीए को मिले 38 प्रतिशत से अधिक ह। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस दल अपने 2014 के वोटिंग शेयर को बढ़ाने में विफल रही और कुल वोटों का 19 प्रतिशत मत ही एकत्र कर सकीं।

भाजपा कि इस लोक सभा चुनावों में जीत के कई कारण हैं, जिनके कारण आज वह देश के सबसे बड़े दल के रूप में पुनः उभरा है । लेकिन प्रमुख कारण जिसने इस शानदार जीत और विपक्ष के पतन को सुनिश्चित किया, वह यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकर्मण्यता एवं करिश्माई व्यक्तित्व को लेकर पक्ष एवं विपक्ष सहित सभी लोग लोहा मानते है।

इसका ही परिणाम रहा है कि उन्होंने भारत के आम जनमानस से जो व्यापक अपील कि उसने लोगों के दिल और दिमाग का जीत लिया। इसके कारणवश पुनः देश कि जनता ने अपने मताधिकार के माध्यम से वापस उन्हें सत्ता के लिए चुना। इस बार के चुनाव का फैसला एक

प्रकार से उनकी सरकार एवं नीतियों का एक सशक्त अनुसमर्थन है। इस चुनाव में बीजेपी के जीत हासिल करने में प्रधनमंत्री मोदी कि व्यक्तिगत कार्यशैली ने मुख्य भूमिका निभाई, क्योंकि देश के आम जनमानस ने देखा कि वह देश के गौरव को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करते हैं।

उन्हें किसी अन्य नेता या किसी अन्य प्रधानमंत्री से अधिक प्रचार करते देखा गया। इसलिए ही लोगों ने चाय विक्रेता की विनम्र शुरुआत से स्व–निर्मित व्यक्ति की उनकी छवि को समझा और उसकी सराहना की। लोग उन्हें एक जन–समर्थक नेता के रूप में देखते हैं, जो अजेय है और किसी भी पारिवारिक संबंधों के कारण राजनीति में नहीं है। जैसा कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ‘‘आकांक्षात्मक भारत रॉयल्टी राजवंश और जाति आधारित दलो को स्वीकार नहों करता है। इस भावना का प्रयोग बीजेपी ने किया और कांग्रेस को एक स्वतंत्र दल के रूप में नहीं बल्कि एक वंशवाद अर्थात् गांधीवाद को दल के रूप में पेश किया और इससे कांग्रेस को हानि पहुंची क्योंकि वे अपने इतिहास में दूसरी सबसे कम सीटों के साथ हार गईं।

इसके विपरोत कांग्रेस दल सम्पूर्ण चुनाव अभियान मतदाताओं पर छाप छोड़ने में विफल रहा। मोदी के विकल्प के रूप में खुद को पेश करने में अपनी असफलता या यूपीए गठबंधन के अलावा इसने कई कमियों को अंजाम दिया। हालाँकि राहुल गाँधी ने स्वयं को एक बड़े रूपांतरित नेता के रूप में पेश किया। लेकिन मोदी जी के खिलाफ उनका चुनावी हमला ”चौकीदार चोर है ” नारे के रूप में टिक नहीं पाया। बीजेपी के कार्यकाल के अंतराल सरकार का आर्थिक प्रदर्शन इस चुनाव में उसका सबसे बड़ा खतरा था– लकिन मोदी इससे बाहर निकलने में सफल रहे। जहाँ 2014 के चुनावों में मोदी का सफल होना विकास की उम्मीद पर आधारित था। उनका नारा था ”सबका साथ–सबका विकास”।

उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने एवं बुनियादी ढांचे में सुधार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वायदा किया। लेकिन उन वायदों पर अमल नहीं हुआ। कथित तौर पर बेरोजगारी बढ़ी और एक रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि संख्या 45 वर्षों में सबसे अधिक थी। इसके अलावा विमुद्रीकरण की दिशा में मोदी का कदम बुरी तरह असफल हुआ जिसके परिणामस्वरूप उन्हें आम लोगों और मध्यम वर्ग के व्यापारियों के क्रोध का सामना करना पड़ा।

यहां अन्य समस्याएं भी भी देखने को मिली हैं– भारत में किसान वर्षों से व्यथित हैं क्योंकि लागत कई बार बढ़ गई है जबकि उनकी आय में कमी आई है या गिरावट आई है।

किसानों द्वारा अपने कर्ज के कारण आत्महत्या करना निराशाजनक हो गया है। 2014 में मोदी को सत्ता में लाने में किसानों की बड़ी भूमिका थी क्योंकि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

हालाँकि इन सब के होते हुए भी इस चुनाव में पहले कि तुलना में अधिक भाजपा ने समाज के सभी वर्गों से समर्थन प्राप्त किया है और इस तथ्य को उजागर किया है कि मतदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी एवं उनकी कार्यशैली पर अब भी भरोसा है। इस तथ्य के बावजूद कि लोगों को उनके पहले कार्यकाल से जो अपेक्षा थी वो लाभ नहीं मिला फिर भी लोग आशान्वित हैं कि यदि दूसरा माका दिया जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री में यह विश्वास तब सिद्ध होता है जब हम आम लोगों से सुनते हैं –''मुझे मोदी के शासन में लाभ नहीं हुआ होगा, लेकिन वह देश के लिए अच्छा है''।

यर्थात् रूप से, ऐसे अन्य कारण भी थे जिन्होंने बीजेपी को नंबर एक स्थान हासिल करने में मदद की जैसे कि– बीजेपी ने सांप्रदायिक आधार पर अपने हिंदू वोटबैंक को सफलतापूर्वक समेकित किया। भारतीय राष्ट्रवाद की चर्चा भाजपा के अभियानों में सबसे आगे थी। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमले और बारह दिन बाद पाकिस्तान के बालाकोट में ''सर्जिकल स्ट्राइक 2.0'' ने पूरे भारत के मतदाताओं के मूड को प्रभावित किया। ''हमने पाकिस्तान को उसके ही इलाके मं घुस कर मारा''– यह कथन एक प्रकार से राष्ट्र की आवाज बन गया और इससे युवाओं में मोदी की लोकप्रियता बढ़ी। मोदी और बीजेपी के खिलाफ किसी भी चीज को राष्ट्र–विरोधी के रूप में देखा गया– यह उनकी अविश्वसनीय लोकप्रियता ही थी।

दल को यह ज्ञात है और इसीलिए उसका अभियान विलक्षण रूप से उस पर केंद्रित था, इस हद तक कि मोदी और केवल मोदी अकेले दल के होर्डिंग पर थे। इसके विपरीत कांग्रेस के प्रचारकों ने कोई नए विचार नहीं पेश किए और दल के नतृत्व की समस्या दूर नहीं हुई। इस चुनाव में बीजेपी ने बड़ी चतुराईता से मोदी बनाम कौन के रूप में चुनाव लड़ा। मोदी ने 2019 के मतदान का नेतृत्व किया और विपक्ष की निर्णायक हार को सुनिश्चित किया और इसीलिए निणायक नेतृत्व का प्रतीक बन गये।

निष्कर्षतः 21 वीं सदी भारत के लिए अवसर एवं चुनौतियों भरी हुई है। मोदी को पुनः सत्ता में लाकर देश कि जनता ने तो अपना कार्य कर दिया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी का दायित्व

पहले कि तुलना में और बढ़ गया है कि वह भारत के जनमानस कि भावनाओं का आदर करें एवं हमारे पूर्वजों ने भारत को जो विश्व गुरु बनाने के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन दान कर दिया उसको स्थापित करने का कार्य करं ताकि आज भारत जो विश्व कि महाशक्ति के रूप में उभर रहा है , वो बन सकें ।

♦♦♦♦♦

5

2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की भूमिका का विश्लेषण

काजल

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव में 37.4 प्रतिशत वोट प्राप्त किए गए। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को लगभग 45 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। यह किसी भी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल या गठबंधन द्वारा व्यापक रूप से प्राप्त किया गया वोट प्रतिशत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में किया गया था। राजग गठबंधन यानी शिवसेना, जनता दल (यूनाइटेड), शिरोमणि अकाली दल, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ लगभग 45 प्रतिशत का संचयी वोट प्रतिशत जीता, जो कि 2014 में मिले 38 प्रतिशत की तुलना में अधिक है।

इसके विपरीत, कांग्रेस पार्टी 2014 से अपने वोट प्रतिशत में सुधार करने में विफल रही और कुल वोटों का 19.5 प्रतिशत ही प्राप्त कर पायी। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने इस प्रकार 2014 से न केवल अपने संबंधित वोट प्रतिशत और सीटों में वृद्धि की, अपितु चुनावी सफलता में अपनी भौगोलिक पहुंच का भी विस्तार किया।

इसके अतिरिक्त यह चुनाव विपक्षी दलों की चुनावी रणनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एवं रोचक रहे। जिसके अंतर्गत यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो चुनाव से पूर्व यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि सबसे बड़ा राज्य होने के कारण और जातिगत रूप से विस्तृत होने के कारण उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनावों में बहुत अहम् भूमिका रही है। परिणामस्वरूप सभी विपक्षी दलों ने आपसी मतभेद समाप्त कर गठबंधन बनाया जिसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना था। परिणामों की दृष्टि से इन चुनावों में सभी का ध्यान इस गठबंधन की ओर अधिक रहा है। इस लेख का उद्देश्य 2019 लोक सभा चुनावों में गठबंधन के रूप में उत्तर प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण कर उसके अंतर्गत जाति की भूमिका को देखना है।

उत्तर प्रदेश में गठबंधन राजनीति का लोकसभा चुनाव पर प्रभाव

समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और राष्ट्रीय लोक दाल (आरएलडी) गठबंधन का प्रभाव यूपी में भाजपा उम्मीदवारों के चयन से स्पष्ट हो गया था, पार्टी ने प्रारम्भ में 61 घोषित सीटों में से 48 को पुनः नामांकित किया था। 13 नए नामों में से छह नाम अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। अधिकांश सांसदों को पुनः नामांकित करने के निर्णय को विद्रोहियों से बचने के लिए एक सावधानी के रूप में देखा गया, जिसने चुनाव को कठिन बनाने का प्रयास किया। क्योंकि उन्हें कोई एंटी–इनकंबेंसी का सामना नहीं करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सदैव जातिगत वोटों के लिए चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण राज्य रहा है। कहीं न कहीं चुनाव पूर्व ऐसा माना गया कि बसपा और सपा के एकीकृत वोटों का सामना कर पाना भाजपा के लिए कठिन होगा। मुख्यतः बसपा के पास वोट स्थानांतरण में एक विश्वसनीय रिकॉर्ड रहा है। हालांकि बसपा के टिकटों के वितरण ने सपा के वर्गों में चिंता उत्पन्न कर दी थी, लेकिन ऐसा अनुमान रहा है कि जाटव मतदाता बसपा के समर्थन में ही रहेंगे, जबकि भाजपा गैर–जाटव दलित वोटो को पाने में लगी थी। गठबंधन ने मूलतः जातिगत रूप से काफी प्रभाव डालने का प्रयास किया परन्तु परिणाम के बाद यह भी सामने आया कि किस प्रकार यह जातीय समीकरण एवं दलीय गठबंधन अपनी ही रणनीति में असफल हो गया।

राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद

2014 में, मोदी लहर के कारण, भाजपा के नेतृत्व में राजग ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 73 पर सफलता प्राप्त की थी, जिसमें अपना दल से सहयोग भी प्राप्त हुआ था। 2019 में, यह अनुमान लगाया गया था कि भाजपा एंटी–इनकंबेंसी के कारण हानि का सामना करेगी, इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता की वास्तविक प्रकृति द्वी–ध्रुवीय थी, जिसमे समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के दुर्जेय जाति गठबंधन के विरुद्ध भाजपा को सामना करना था और इन सभी दलों पर बढ़त प्राप्त करनी थी। जो राजग द्वारा 62 सीटों के साथ प्राप्त की गयी और 2014 के चुनावों की तुलना में 41 प्रतिशत से, 2019 के चुनावों में 50 प्रतिशत से थोड़ा कम तक पहुँच पाई। इसके अतिरिक्त बसपा का गठबंधन 37.2 प्रतिशत वोट शेयर करने के साथ 15 सीटें जीतने में सफल रहा, और तीसरे खिलाड़ी के रूप में, कांग्रेस को मात्र एक, सोनिया गांधी की रायबरेली सीट को बचा सकी। इसके अतिरिक्त इस गठबंधन की महत्वपूर्ण बात यह थी कि जातिगत दृष्टि से बसपा और सपा ने क्रमशः 38 और 37 सीटों पर चुनाव लड़ा और ओबीसी तथा पिछड़ी जाति समूह में अपना पक्ष मजबूत रखने का प्रयास किया, वहीं

आरएलडी ने पश्चिमी यूपी में तीन सीटों पर चुनाव लड़ा, जो जाट बहुल क्षेत्र होने के कारण उसका पारंपरिक गढ़ है। यह चुनाव मुख्य रूप से जातिवाद बनाम राष्ट्रवाद के रूप में देखा गया, जिसमें जीत राष्ट्रवाद की हुई जिसके कारण निम्नलिखित है:–

1. बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार "पश्चिमी के साथ–2 पूर्वी यूपी में भी मोदी के समर्थन में उच्च वर्गीय और अत्यधिक पिछड़ी जाति समूह के व्यक्तियों का एकीकरण था, जबकि ओबीसी में केवल यादव और दलित जाति में केवल जाटव ने महागठबंधन का समर्थन किया, जिसमे मुस्लिम वर्ग भी शामिल था।
2. राजनीतिक वैज्ञानिक और प्रोफेसर गिलेस वर्नियर्स का कहना है कि गठबंधन अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन करने में विफल रहा है और इसका कारण यह है कि पार्टियों ने मतदाताओं के बीच केवल अपने मूल आधार पर ध्यान केंद्रित किया। महागठबंधन के लिए जो गलत हुआ वह यह है कि यह सभी मतदाताओं के लिए एक प्रस्ताव के बजाय तीन दलों के मूल समर्थन आधारों का गठबंधन था। उनके द्वारा केवल अपने पारंपरिक समर्थकों को जुटाने पर ही ध्यान केंद्रित किया गया और उनके वोट उन्ही के बीच विभाजित हो गए व नए मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करना भूल गए।
3. इसके अतिरिक्त बालाकोट पर भाजपा के आक्रामक अभियान और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामान्य विषय ने भी पार्टी के लिए काम किया, जिसने सारा ध्यान और ऊर्जा मोदी पर केंद्रित किया, जबकि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को प्रस्तुत करने में महागठबंधन की अक्षमता पर भी भाजपा का हमला जारी रहा। परिणामस्वरुप जाति अंकगणित के अतिरिक्त, महागठबंधन में नीति के संदर्भ में दिशा का अभाव था।

कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस के बीच महागठबंधन केवल अपने प्रमुख समर्थकों पर केंद्रित था, हालाँकि गठबंधन ने भाजपा के वोट प्रतिशत पर काफी प्रभाव भी डाला परन्तु कहीं न कहीं गठबंधन दल यूपी के सभी मतदाताओं पर ध्यान देना भूल गया। इसके विपरीत भाजपा ने स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा की लहर को मोदी के चेहरे के साथ अपनी चुनावी रणनीति में शामिल किया, जिसके विपरीत विपक्ष कोई एक स्पष्ट पीएम उम्मीदवार की पसंद को लोगो के समक्ष रखने में असफल रहा। परिणामस्वरूप पुनः भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जीत प्राप्त की।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन
गुरू तेग बहादुर मार्ग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली–110007

www.dcrc.du.ac.in office@dcrc.du.ac.in @dcrcofficial +91-11-27666281